



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2055, वर्ष 2026

शफीक

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमन कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार

पाण्डेय, विवेक कुमार शुक्ला

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान ज़मानत अर्ज़ी अभियुक्त-आवेदक द्वारा आपराधिक वाद संख्या 606/2025 में ज़मानत की माँग करते हुए दायर की गई है, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(b)(i)/3 के तहत, पुलिस थाना- पडुआ, ज़िला- लखीमपुर खीरी में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध मात्र एक ही मामला दर्शाया गया है, जिसमें वह ज़मानत पर है। ज़मानत आदेश, ज़मानत अर्ज़ी के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के साथ अनुलग्नक-3 के रूप में अभिलेख पर उपस्थित है। गैंग चार्ट में उल्लिखित वाद (वादों) के अतिरिक्त, आवेदक का कोई अन्य पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 26.2.2026 से जेल में है।

यह भी निवेदन है कि आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या साक्षियों के साथ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

इन तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद कि आवेदक 26.2.2026 से जेल में है; आवेदक को गैंग चार्ट में दिखाए गए वाद में ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है; और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त प्रकरण मानता हूँ।

तदनुसार, ज़मानत अर्ज़ी **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त आपराधिक वाद /प्राथमिकी संख्या में सम्मिलित आवेदक—**शफीक** को, न्याय के हित में लगाई जा रही निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी बंध-पत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए :-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक विचारण के समय साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह किसी भी स्थगन की माँग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (v) आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की अपेक्षाओं के अनुरूप, एक वचनपत्र

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भी प्रस्तुत करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) आवेदक, निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि आवेदक विचारण के समय जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

31 मार्च, 2026

श्रवण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।